THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) Representations were made by several State Governments before the Study Group appointed by the Central Govt. to consider revision of royalty rates on coal. While the Govt. of Bihar represented for fixation of ad-valorem rates of royalty on coal between 45% to 55%, the Govts. of Madhya Pradesh, Assam and West Bengal represented for fixation of ad-valorem rates at 20% of coal price. Govt. of Karnataka represented for limiting the total taxes levied on coal to 5% ad-valorem.

Govts. of Orissa and Maharashtra suggested continuation of specific rates of royalty on coal.

(c) The suggestion for fixation of royalty on ad-valorem basis did not find favour with the Study Group. After taking into consideration the report of the Study Group, the Government revise the rates of royalty on coal w.e.f. 11.10.1994, raising the average royalty rate for coal produced by Coal India Ltd. from Rs. 70 per tonne to Rs. 86.40. per tonne.

कोल इंडिया लिमिटेड के भ्रष्ट अधिकारी

1975. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० के कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले आये हैं और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने मामलों का निपटारा कर लिया गया है; और

(ख) उपर्युक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारी और पदाधिकारी दोषी पाये गये और किन-किन अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और प्रत्येक मामले में किस तरह की कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के विरुद्ध 294 मामले आरंभ किए गए हैं तथा ऐसे 120 मामलों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

91 अधिकारियों के मामले में अभी तक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:—

कार्रवाई	अधिकारियों की संख्या
अभियोजन	23
भारी दंड	14
हल्का दंड	34
दोषमुक्ति	4
प्रशासनिक कार्रवाई	14
चेतावनी	2
जोड़:	91

उन अधिकारियों, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके नाम बताना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि उन्हें की गई कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी रूप में सहायता प्राप्त करने अथवा विभागीय रूप से अपीलीय प्राधिकारियों के सम्मुख अपना पक्ष रखने का अधिकार है।

Outstanding arrears of CIL

1976. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what are the total arrears to Coal India Limited towards supply of coal as on date;

(b) out of the total arrears, how much are from State Electricity Boards, Railways and other public and private Sector establishments; and;

(c) what action has been taken to recover the dues?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) As on 28.2.95 the total amount of outstanding dues to Coal India Ltd. from all consumers on account of coal supplies was Rs. 4294 crores (provisional). The sector-wise break up of this is as below:

(Rs. in crores)

(i) State Electricity Boards	1969
(ii) Railways	66